गहराता जल संकट

बीते कुछ वर्षों से कमतर बारिश और सूखे की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में जल संकट बढ़ता जा रहा है. कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय जल आयोग ने जलाशयों के गिरते जलस्तर पर चिंता व्यक्त की थी. बीते एक दशक में जलाशयों में औसत जल संग्रहण में 20 प्रतिशत की कमी आ चुकी है. आज जब देश जल संकट के अब तक के सबसे भयावह दौर के मुहाने पर है, तब मॉनसून-पूर्व बारिश के कम होने से चिंताएं बढ़ गयी हैं. आइआइटी, गांधीनगर द्वारा संचालित सूखा चेतावनी प्रणाली ने पहले ही बता दिया है कि 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में सूखे के स्पष्ट संकेत उभर रहे हैं. देशभर में मॉनसून-पूर्व बारिश (मार्च से मई माह के बीच) में 23 प्रतिशत की कमी रही है, जो बीते छह वर्षों में सबसे कम है. एक अनुमान के मुताबिक इस बार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल में चार से पांच दिन की देरी से दस्तक देगा. बारिश की कमी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों के लिए समस्या बढ़ा सकती है. मॉनसून के कमजोर रहने का सीधा मतलब खेती के लिए खतरे की आहट. एक उम्मीद यह है कि अगर प्रशांत महासागर के तापमान में कमी आती है, तो दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अवधि का दूसरा हिस्सा बेहतर हो सकता है. अलनीनो के कमजोर रहने का अनुमान भी आशा की एक किरण है. देश के लगभग हर भाग में लगातार बढ़ते जा रहे जल संकट से निपटने के लिए हमें जल स्रोतों और जलाशयों, भूजल तथा सिंचाई संसाधनों का विवेकपूर्ण और उचित उपयोग सीखना होगा. बीते दशक में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों और उपभोग की बदलती आदतों से वैश्विक स्तर पर जल की खपत हर साल एक फीसदी की दर से बढ़ रही है. जलवायु परिवर्तन और औसत तापमान में बढ़ोतरी की वजह से भी कई क्षेत्रों में सूखापन बढ़ रहा है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 20 से अधिक शहरों में भूजल स्तर की गिरावट समस्याग्रस्त भविष्य का स्पष्ट संकेत है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले एक वर्ष में जलसंकट की इस समस्या से 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, वहीं 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी इस गंभीर समस्या की चपेट में होगी. इस आसन्न संकट से निपटने के लिए ठोस पहल की जानी चाहिए. सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने, वर्षा जल का संग्रहण और पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा. जल प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए भी बड़े स्तर पर मुहिम चलानी होगी. पानी के संरक्षण, संग्रहण और उपयोग पर व्यापक नीति बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर ध्यान दिये बिना जल संकट का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता है.

पानी के संरक्षण, संग्रहण और उपयोग पर व्यापक नीति बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय पर ध्यान दिये बिना जल संकट का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता है.

वंशवाद समाप्त नहीं हुआ है

एक कार्टून इन दिनों सोशल साइटों में वायरल हो रहा है. राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की गोद में बैठकर अशोक गहलोत, पी चिदंबरम और कमलनाथ की ओर अंगुली उठाकर कह रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटों को टिकट देने की जिद की. इस्तीफे तक की धमकी दी. बताते हैं कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल ने क्षोभ के साथ यह बात कही थी. कार्टूनिस्ट का तंज स्वाभाविक है कि राजनीति में वंशवाद के सबसे बड़े प्रतीक स्वयं राहुल गांधी हैं.

बहरहाल, राहुल अमेठी की अपनी पारिवारिक सीट से चुनाव हार गये. चुनाव हारनेवालों में कुछ बड़े चर्चित परिवारवादी भी हैं. पत्नी, बेटों और बेटी को राजनीति में स्थापित करनेवाले लालू यादव के परिवार का इस बार एक भी सदस्य नहीं जीता. बहुचर्चित परिवारवादी मुलायम सिंह यादव और उनके बड़े बेटे अखिलेश चुनाव जीत गये, लेकिन उनकी बहू और भतीजे हार गये. अजित सिंह और उनके बेटे जयंत हार गये. कर्नाटक में देवगौड़ा स्वयं और उनके परिवारीजन खेत रहे. राजनीति में स्थापित एक और बड़े परिवार के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाये.

परिवारवादी राजनीति की पराजय के ऐसे कुछ अन्य उदाहरणों के आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार की मोदी लहर ने राजनीति से वंशवाद का सफाया कर दिया. क्या वास्तव में ऐसा हुआ है?

पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का और तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार जीत गया. मोदी लहर में भी कमलनाथ छिंदवाड़ा की अपनी पुरानी सीट से बेटे को जिता ले गये. सोनिया गांधी जीतीं और अमेठी से हारनेवाले उनके बेटे राहुल वायनाड सीट से लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे. धमाके से जीतनवाले आंध्र के जगनमोहन रेड्डी और उड़ीसा के नवीन पटनायक लोकप्रिय नेताओं के वंशज ही हैं. सूची लंबी है.

'इंडियन एक्सप्रेस' में तीन दिन पहले प्रकाशित एक शोध-रपट के अनुसार, सत्रहवीं लोकसभा में पहुंचे सांसदों में 30 प्रतिशत राजनीतिक परिवारों के हैं. यह नया कीर्तिमान है. साल 2004 से 2014 तक यह करीब 25 फीसदी था. राजनीतिक दलों में सर्वाधिक वंशवादी कांग्रेस ही है, जिसके इस बार 31 प्रतिशत उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों के थे. आश्चर्य है कि कांग्रेस पर परिवारवाद का तीखा आरोप लगानेवाली भाजपा स्वयं इस मामले में कांग्रेस का मुकाबला करने की तरफ बढ़ रही है. इस बार इसके 22 फीसदी उम्मीदवार परिवारवादी थे. उसका यह आंकड़ा हर चुनाव में बढ़ रहा है.

राजनीति में परिवारवाद पनपने के कारण हैं. आजादी के बाद राजे-रजवाड़ों ने चुनावी राजनीति में शामिल होकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की. उनकी लोकप्रियता और भारतीय समाज की संरचना ने उन्हें राजनीति में स्थापित कर दिया. उनके वंश राजनीति में फले-फूले. राजनीतिक दलों ने उनके जीतने की बेहतर संभावना के कारण उन्हें आगे बढ़ाया. आजादी के इतने वर्ष बाद भी रजवाड़ों की संततियां राजनीति में सक्रिय हैं.

कांग्रेस थोड़ा अलग तरह का उदाहरण है. नेहरू पर सीधे यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने अपनी बेटी को कांग्रेस का उत्तराधिकार सौंपा. इंदिरा गांधी पार्टी के भीतर 'ओल्ड गार्ड' से लड़कर कांग्रेस पर काबिज हुईं. हां, खुद उन्होंने कांग्रेस को इतना बौना बना दिया कि बेटे संजय की मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए वे बड़े बेटे राजीव को उनकी अनिच्छा और बहू सोनिया के विरोध के बावजूद विमान के कॉकपिट से उठा लायीं. वह शायद सबसे बढ़िया अवसर था, जब कांग्रेस अपना गैर-नेहरू-गांधी उत्तराधिकारी चुन सकती थी. लेकिन तब तक कांग्रेस में इतना ताब ही नहीं बचा था. अब तो कांग्रेस इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती.

नवीन जोशी
वरिष्ठ पत्रकार
naveengjoshi@gmail.com

लोकतंत्र में परिवारवाद की जगह नहीं होनी चाहिए. पार्टी संगठन के चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से हों, तो परिवारवाद का बोलबाला कम होगा और सक्षम नेतृत्व उभरेगा. पार्टियों पर परिवारवाद के कब्जे ने अनेक प्रतिभाशाली नेताओं को दबाया है.

परिवारवाद का एक नया संस्करण मंडल-राजनीति से उभरे मध्य जातियों के ताकतवर क्षेत्रीय क्षत्रपों ने स्थापित किया. विशेष रूप से मुलायम और लालू यादव ने अपनी पार्टियों को प्राइवेट कंपनियों की तरह चलाया. कर्नाटक और तमिलनाडु में भी ऐसा ही दौर आया. ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, यानी लगभग सभी राज्यों में बड़े नेताओं के परिवारीजन पार्टी में ऊपर से थोपे जाते रहे. सिर्फ वाम दल इसके अपवाद हैं.

जेल में बंद सजायाफ्ता बाहुबली कानूनन चुनाव न लड़ पाने पर अपनी पत्नियों को मैदान में उतार देते हैं. चारा घोटाले में अदालत में आरोपित किये जाने के बाद 1997 में लालू यादव ने रातोंरात मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी पर पत्नी राबड़ी देवी को बैठा दिया था. कुछ राजनीतिक परिवारों में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयां भी हुईं. शिव सेना, द्रमुक, सपा और राजद में ऐसे झगड़े हो रहे हैं, जो पारिवारिक संपत्ति के लिए होनेवाले संघर्षों की याद दिलाते हैं.

लोकतंत्र में परिवारवाद की जगह नहीं होनी चाहिए. पार्टी संगठन के चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से हों, तो परिवारवाद का बोलबाला कम होगा और सक्षम नेतृत्व उभरेगा. पार्टियों पर परिवारवाद के कब्जे ने अनेक प्रतिभाशाली नेताओं को दबाया है. ऐसी पार्टियों में कोई 'बाहरी' सक्षम नेता संगठन के चुनाव लड़ने की कल्पना नहीं कर सकता. अगर कोई पार्टी अपने भीतर ही लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उसके आदर पर स्वाभाविक ही संदेह होगा.

कांग्रेस का नेतृत्व दशकों से नेहरू-गांधी परिवार के हाथों में है. भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी परिवारवादी नहीं हुआ है, लेकिन उसके कई नेता अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं. दोनों ही राष्ट्रीय दल परिवारवादियों को चुनाव लड़ाने में आगे हैं. ऊपर जिस रिपोर्ट का उल्लेख हुआ है, उसके निष्कर्षों ने इस भ्रांति को तोड़ा है कि क्षेत्रीय दल ही राजनीति में परिवार को बढ़ावा देने में आगे हैं. जबकि सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय दल अग्रणी हैं. इस बार क्षेत्रीय पार्टियों के 12 प्रतिशत उम्मीदवार परिवारवादी थे, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों का यह आंकड़ा 27 फीसदी है.

तथ्य यह भी है कि राजनीतिक परिवारों के वंशजों का चुनाव जीतने का औसत सामान्य प्रत्याशियों के विजयी होने के औसत से अधिक है. उसी रिपोर्ट के अनुसार, इस बार चुनाव में 2189 उम्मीदवारों में 389 यानी 18 प्रतिशत राजनीतिक परिवारों के थे, जबकि जीतकर लोकसभा पहुंचनेवालों का प्रतिशत 30 (542 में 162) है. यह तथ्य स्पष्ट करता है कि सभी दल वंशवाद का पोषण क्यों करते हैं और क्यों इसकी निंदा करनेवाली भाजपा भी इसी राह पर है. अर्थात, यह कहना सही नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में वंशवाद समाप्ति की ओर है.

बोधि वृक्ष

तुम्हारा इरादा

इस संसार की कोई भी तकनीक काम नहीं करती! वह तो तुम हो, जिसके कारण सारी तकनीकें काम करती हैं. तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम तकनीक खोजते हो और वह काम करने लगती है. जब तुम इरादा करते हो और उस पर तुम ध्यान देते हो, तो सब कुछ वैसा होने लगता है. अगर तुम्हारा इरादा नहीं है, तो वह काम नहीं करेगी. ठीक इसी तरह से सुदर्शन क्रिया का प्रभाव होता है, क्योंकि उसके पीछे इरादा है. किसी भी काम की पूर्ति के लिए उसके लिए इरादा, फिर उस पर ध्यान देना जरूरी है, तभी वह होने लगता है. अब कुछ प्राणायाम के बारे में बात करते हैं. नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करते हैं. जब हमारी बाहिनी नासिका सक्रिय होती है, तो दिमाग का दाहिना हिस्सा सक्रिय होता है, और जब दाहिनी नासिका सक्रिय होती है, तो दिमाग का बाहिना हिस्सा सक्रिय होता है. दिमाग का दाहिना हिस्सा संगीत है और दिमाग का बाहिना हिस्सा तर्क. तो जिनकी दाहिनी नासिका सक्रिय है, वे मुझे बेहतर समझ सकते हैं. और अगर दोनो सक्रिय हैं, तो आप ध्यान में हैं. केवल दाहिनी नासिका सक्रिय होने से ध्यान नहीं होता. जब भी आप अपनी आंखे बंद करते हैं या खोलते हैं, तो आपकी स्थिति बदल जाती है. भोजन के बाद दाहिनी नासिका सक्रिय होनी चाहिए. जब दाहिनी नासिका सक्रिय होती है, तो पाचन प्रक्रिया पचास प्रतिशत तेज होती है. बाहिनी यां दाहिनी नाड़ी की सक्रियता बदलती रहती है, क्योंकि हम प्राणों के सागर में रहते हैं. किस समय कौन सी नासिका सक्रिय होगी, यह स्थान और वातावरण पर निर्भर करता है. अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या किसी भी ऐसी जगह के पास जाते हैं, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक है, तो दोनों नासिकाएं सक्रिय हो जाती हैं. जब किसी पूजा के स्थान पर लोग पूर्ण भक्ति में होते हैं, तब भी ऐसा होता है. जब आप किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं, तो भी ऐसा होता है. जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपकी आवाज आपको स्वयं बता देगी.

श्रीश्री रविशंकर

'प्रताप' का अविचलित प्रतिरोध

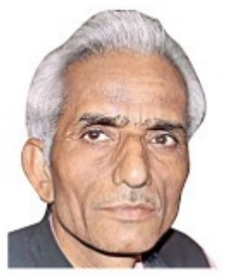

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

30 जुलाई, 1921 को अव्वल दर्जा मजिस्ट्रेट मकसूद अली खां ने प्रताप के संपादक और मुद्रक दोनों को एक-एक हजार रुपये के जुर्माने और छह-छह महीने की कैद की सजा सुना दी. लेकिन न 'प्रताप' ने अपना रास्ता बदला, न ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने.

कोलकाता में सक्रिय कानपुर के वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा 1826 में आज के ही दिन यानी 30 मई को बड़ा बाजार के पास स्थित 37, अमर तल्ला लेन, कोलूटोला (कोलकाता) से 'हिंदुस्तानियों के हित' में साप्ताहिक 'उदंत मार्तंड' के प्रकाशन से हिंदी पत्रकारिता की जो परंपरा शुरू हुई, सच्चे मायनों में वह अन्यायी सत्ताओं के प्रतिरोध की ही रही है. देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम से तीन साल पहले 1854 में श्यामसुंदर सेन द्वारा प्रकाशित व संपादित हिंदी के पहले दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' ने प्रतिरोध की इस परंपरा को प्राणप्रण से समृद्ध करना आरंभ किया, तो अंग्रेजों ने उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर अदालत में खींच लिया. लेकिन उसके संपादक श्यामसुंदर सेन ने ऐसी कुशलता से अपना पक्ष रखा कि अंग्रेजों की अदालत ने ही देश पर अंग्रेजों के कब्जे को गैरकानूनी करार दे दिया. आगे चलकर इस परंपरा का अलम अपनी तरह के अनूठे स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित कानपुर के दैनिक 'प्रताप' के हाथ आया, तो उसने भी गोरी सत्ता की आंखों की किरकिरी बनने में कुछ भी उठा नहीं रखा. उसे क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उसे उसके पथ से विचलित नहीं कर सका.

दरअसल, अवध में अंग्रेजों और उनके 'आज्ञाकारी' तालुकेदारों के अत्याचारों से त्रस्त किसान 1920-21 में हिंसक आंदोलनों पर उतर आये, तो गोरी सत्ता ने उनका तो बेरहमी से दमन किया ही, उनका पक्ष लेनेवाले समाचारपत्रों और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा. इनमें अपनी खुली किसान पक्षधरता के कारण 'प्रताप' उनके दमन का कुछ ज्यादा ही शिकार हुआ, क्योंकि वह पूरी तरह देश की आजादी और किसान हितों को समर्पित था. उसका ध्येयवाक्य था- 'दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे.' उसकी संपादकीय नीति अंग्रेजों को इतनी भी गुंजाइश नहीं देती थी कि वे आजादी के लिए गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे अहिंसक और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित सशस्त्र अभियानों के अंतर्विरोधों का लाभ उठा सकें. उसमें इन दोनों ही तरह के अभियानों का लगभग एक जैसा समर्थन और सम्मान किया जाता था.

अंग्रेजों की सेना और पुलिस ने सात जनवरी, 1921 को अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे किसानों को रायबरेली शहर के मुंशीगंज में सई नदी पर बने पुल पर रोका और गोलियों से भून डाला, तो प्रताप पहला ऐसा पत्र था, जिसने उसे 'एक और जलियांवाला' की संज्ञा दी. उन दिनों के हालात में यह अपने विनाश को आमंत्रित करने जैसा था. यह जानते हुए भी 'प्रताप' के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने 13 जनवरी, 2021 के अंक में 'डायरशाही और ओ डायरशाही' शीर्षक अग्रलेख लिखा, तो अंग्रेज न सिर्फ तिलमिला गये, बल्कि बदला लेने पर उतर आये. विद्यार्थी ने लिखा था- 'ड्यूक ऑफ कनाट के आगमन के साथ ही अवध में जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति शुरू हो गयी है, जिसमें जनता को कुछ भी न समझते हुए न सिर्फ उसके अधिकारों और आत्मा को अत्यंत निरंकुशता के साथ पैरों तले रौंदा, बल्कि उसकी मान-मर्यादा का भी विध्वंस किया जा रहा है. डायर ने जलियांवाला बाग में जो कुछ भी किया था, रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुंशीगंज में उससे कुछ कम नहीं किया. वहां एक घिरा हुआ बाग था और यहां सई नदी का किनारा और क्रूरता, निर्दयता और पशुता की मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं थी.'

यही नहीं, 'प्रताप' ने रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एजी शेरिफ के चहेते एमएलसी और खुरेहटी के तालुकेदार वीरपाल सिंह की, जिसने मुंशीगंज में किसानों पर फायरिंग शुरू की थी, 'कीर्तिकथा' छापते हुए उसे 'डायर का भाई' बताया और यह जोड़ना भी नहीं भूला कि 'देश के दुर्भाग्य से इस भारतीय ने ही सर्वाधिक गोलियां चलायीं.' फिर तो अंग्रेजों ने वीरपाल सिंह को मोहरा बनाकर उसके संपादक व मुद्रक को मानहानि का नोटिस भिजवाया और उनके क्षमायाचना न करने पर रायबरेली के सर्किट मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दायर करा दिया.

इस मुकदमे में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार और अधिवक्ता वृंदावनलाल वर्मा ने 'प्रताप' की पैरवी की. उन्होंने 65 गवाह पेश कराये, जिनमें राष्ट्रीय नेताओं मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और विश्वंभरनाथ त्रिपाठी के अलावा किसान और महिलाएं थीं. रायबरेली के कई डॉक्टरों, वकीलों और म्युनिसिपल कमिश्नरों ने भी 'प्रताप' की खबरों की सच्चाई की पुष्टि की. बाद में जिरह में गणेश शंकर विद्यार्थी ने खुद भी अपना पक्ष रखा और लिखित उत्तर में कहा कि उन्होंने जो कुछ भी छापा, वह जनहित में था और उसके पीछे संपादक या लेखक का कोई खराब विचार नहीं था. वे वीरपाल को व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं थे. 22 मार्च, 1921 को अपनी बहस में वृंदावनलाल वर्मा ने भी उनका जोरदार बचाव किया.

इस सबके बावजूद 30 जुलाई, 1921 को अव्वल दर्जा मजिस्ट्रेट मकसूद अली खां ने प्रताप के संपादक और मुद्रक दोनों को एक-एक हजार रुपये के जुर्माने और छह-छह महीने की कैद की सजा सुना दी. लेकिन न 'प्रताप' ने अपना रास्ता बदला, न ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने. अपने संपादनकाल में विद्यार्थी जी ने पांच बार जेलयात्राएं कीं और 'प्रताप' से बार-बार जमानत मांगी गयी.

आपके पत्र

अपना रवैया बदलें ममता दीदी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी लगातार गलत फैसले लेकर पहले ही अपना जनाधार कम कर चुकी हैं. अभी भी वे न जिद छोड़ रही हैं, न समय की नजाकत को समझ रही हैं. शपथ ग्रहण में न जाकर वे अपनी ही छवि को धक्का पहुंचा रही हैं. जय श्री राम जैसे सामान्य धार्मिक नारे पर ओवर रिएक्शन कर पहले ही काफी क्षति पहुंच चुकी है. वे सिर्फ वोट के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता करती हैं. अफसोस की बात यह है कि पार्टी में कोई उन्हें सही राय देने वाला नहीं. 2014 में भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में खुद नहीं गयी थीं, उससे मोदी का क्या नुकसान हुआ? इस तरह की हरकतों से जननेता जनता की नजर में अपना सम्मान खोते हैं. उनको सोचना चाहिए कि जब वे खुद हर साल जोर-शोर से अपने कार्यकर्ताओं का शहीद दिवस मना सकती हैं, तो भाजपा अपने शहीद कार्यकर्ताओं के परिजनों को सम्मान क्यों नहीं कर सकती? ममता जी को अपना रवैया बदलना चाहिए.

शिखर चंद जैन, कोलकाता

विज्ञापन में सुरक्षा का हो उल्लेख

सूरत की घटना ने आज देश के सारे कोचिंग संस्थानों की पोल खोल कर रख दी है. सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिये हैं. अक्सर अखबारों में कोचिंग संस्थानों के आकर्षक विज्ञापनों की भरमार रहती है. यहां तक कि हर गलियों में, चौक-चौराहों आदि स्थानों में लुभावने पोस्टर और होर्डिंग्स लगे रहते हैं. सभी अपने संस्थान को सबसे बढ़िया बतलाते हैं, परंतु किसी भी संस्थान के विज्ञापन और पोस्टर में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी का उल्लेख नहीं किया जाता. इन संस्थानों को अपने विज्ञापनों में भी सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करना चाहिए जिससे कि इन लुभावने पोस्टर, बैनर से कोचिंग संस्थानों के नाम, उत्कृष्टता के साथ वहां के सुरक्षात्मक व्यवस्था की जानकारी अभिभावकों को हो जाये. इससे उन्हें अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित कोचिंग सेंटर चुनने में मदद होगी.

किशोर चंद्रा, रातू

शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे नयी सरकार

लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि लोगों को इस मोदी सरकार और उनके नेतृत्व पर विश्वास है. अब सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आम जनता की उम्मीदों को ठेस न पहुंचे. उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए कृतसंकल्प रहे. ऐसे में नयी सरकार को प्राथमिकता के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में ठोस बदलाव लाने होंगे. इस क्षेत्र की विसंगतियां को जल्द दूर किये जाने की जरूरत है. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रकल्पों पर बल देना होगा. अस्पतालों में चिकित्सक, दवाएं और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने पर गंभीरता दिखानी होगी जिससे लोग स्वास्थ्य लाभ कर सकें. भारत की सदी बनाने के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कायाकल्प को सुनिश्चित करना होगा.

डॉ मनोज 'आजिज', आदित्यपुर, जमशेदपुर

कुछ अलग

विज्ञापनों में पापा

मुकुल श्रीवास्तव
टिप्पणीकार
sri.mukul@gmail.com

आजकल स्मार्ट होने का जमाना है. शरीर और चीजों को तो स्मार्ट बनाया जा सकता है, लेकिन जब बात महिलाओं की हो, तब हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम वाकई स्मार्ट समय में जी रहे हैं? तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है, अगर उतनी ही तेजी से हमारी मानसिकता बदलती, तो दुनिया ज्यादा खुबसूरत दिखती.

एक छोटा सा उदाहरण है. मेरे पास अक्सर एक एसएमएस आता है. मेरा नाम एबीसी (लडकी का नाम) है, अगर आप अकेले बोर हो रहे हो, तो मुझे इस नंबर पर फोन करो. मैं इस एसएमएस को पढ़कर डीलीट कर देता हूं. मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आखिर इस तरह के विज्ञापन संदेशों की जरूरत क्यों है? मजेदार बात है कि ऐसे एसएमएस लड़कियों को भी भेजे जाते हैं, कायदे से तो उनके पास लड़कों के नाम से एसएमएस भेजे जाने चाहिए और दूसरी बात यह कि क्या बातें करने के लिए लड़कियां ही फ्री बैठी रहती हैं. हमारे समाज में लोगों के जेहन में क्या चल रहा है, यह एसएमएस उसकी बानगी भर है, क्योंकि ऐसे एसएमएस विज्ञापन हवा में नहीं बनते, बल्कि कहीं न कहीं समाज में एक सोच है कि लड़कियों से रोमांटिक बात करना पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार है. पर यही हरकत अगर कोई लड़की शुरू कर दे, तो क्या होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है. लड़कियों को जितनी तेजी से हमारा समाज कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, उसकी आधी तेजी भी लड़कों के लिए आ जाये, तो देश की लड़कियों का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाये.

जरा याद कीजिये अपने मोहल्लों के चौराहों से लेकर दुकानों तक सुबह-शाम लड़के झुंड लगाये आती-जाती लड़कियों को घूरते, फब्तियां कसते अपने स्मार्ट फोन के साथ जीवन का आनंद उठाते दिखते हैं कि नहीं दिखते. इससे एक बात तो साबित होती है कि हमारे समाज में लड़कियां नहीं लड़के ज्यादा फ्री रहते हैं, न तो उन्हें घर के सामान्य कामकाज करने होते हैं न ही उनके किसी काम पर समाज से तुरंत कैरक्टर सर्टिफिकेट मिलने का डर होता है. अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए लड़कियों को अकेले छोड़ दिया जाता है. यानी विज्ञापन भी जेंडर स्टीरियो टाइपिंग का शिकार हैं, क्योंकि उनको बनानेवाले भी इसी समाज के लोग हैं और उनकी मानसिकता भी वैसी बन गयी है. एसएमएस विज्ञापन से आगे टीवी विज्ञापनों पर चलें, तो वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां लैंगिक असमानता साफ साफ दिखती है.

आप भी सोच रहे होंगे कि बात तो स्मार्ट गैजेट से शुरू हुई थी, पर मामला इतना गंभीर हो गया. जी हां, स्मार्ट तकनीक भी स्मार्ट सोच के साथ अच्छी लगती है. नहीं तो फिर 'बंदर के हाथ में उस्तरा' जैसी बात हो जायेगी. जरा सोचिये, कैसा हो जब किसी सूप के विज्ञापन में पापा भूख शांत करायें या डायपर में भी पापा ही बच्चे को अच्छी नींद सुलायें. हृदय को स्वस्थ रखनेवाले विज्ञापन में पत्नी की सेहत का ख्याल पति भी करे. बाकी सभी विज्ञापनों में भी महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी कदम से कदम मिलाकर चलते दिखें!

देश दुनिया से

भ्रष्टाचार के मामले में नजीब पर मुकदमा

हममें से वे सभी, जो मलेशिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एकदम आगे रहे हैं, उनके लिए पिछला महीना ऐतिहासिक रहा. मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को आखिरकार उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों भ्रष्टाचार के मामलों में से एक में मुकदमे का सामना करना पड़ा. नजीब पर आरोप है कि उन्होंने 1एमबीडी संप्रभु धन कोष से सैंकड़ों मिलियन डॉलर गैरकानूनी तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए निकाला. पिछले वर्ष जून में नजीब की बैरिसन नेशनल गठबंधन को चुनाव में हार के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिससे 61 वर्षों से सत्ता पर बनी उनकी पकड़ खत्म हो गयी. पुलिस ने उनके घर से छापेमारी में 273 मिलियन डॉलर नकद और 10 मिलियन डॉलर मूल्य के सामान जब्त किये थे. अप्रैल में हुई सुनवाई 1एमबीडी सब्सिडियरी से संबंधित थी, जबकि मुख्य मामले की सुनवाई अगस्त में शुरू होगी. मलेशिया में ऐसे घोटालों की सूची लंबी है. मारा, फेल्डा, ताबुंग हाजी जैसे तमाम ऐसे सरकारी निकाय हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. अपने शासन के अंतिम दिनों में नजीब जवाबदेही वाले पदों व संस्थानों पर लगाम लगाने में व्यस्त रहे. उन दिनों भ्रष्टाचार के मामले उठाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है